

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोकसभा  
अतारांकित प्रश्न सं0 3083  
12 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

पीएमएवाई पर रिपोर्ट

3083. श्री एस. आर. पार्थिवनः

श्री एच. वसंतकुमारः

डॉ. ए. चेल्लाकुमारः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देशभर में प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत निर्मित मकानों की संख्या से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करेगी तथा यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएमएवाई के तहत विशेष रूप से मछुआरा/गैर-मछुआरा समुदाय के लिए आवासों के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे/आवंटित ईडब्ल्यूएस की संख्या आज की तिथि तक कितनी है;

(ग) देशभर में सभी ईडब्ल्यूएस के लिए जल्द से जल्द आवासों का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में निधि आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : वर्ष 2022 तक "सबके लिए आवास" के सरकार के विजन के अनुपालन में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई (यू)] का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि सभी पात्र शहरी परिवारों, विशेषकर आर्थिक रूप से

कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों/लाभार्थियों को सभी मौसम अनुकूल आवास मुहैया कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा सके। आवास की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आवास की वास्तविक मांग का निर्धारण करने के लिए स्कीम के तहत मांग सर्वेक्षण किया है और अब तक वैध मांग लगभग 112 लाख है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त किए गए परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, स्कीम के तहत कुल 103,61,738 आवास स्वीकृत किए गए हैं; इनमें से 61,57,734 आवास निर्माण के विभिन्न चरणों पर हैं और 32,15,926 आवास पूरे हुए हैं/सुपुर्द किए जा चुके हैं।

पीएमएवाई (यू) के तहत निर्मित कुल आवासों के साथ पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के दौरान निर्मित आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण अनुलग्नक-। पर है।

(ख) से (घ) : पीएमएवाई (यू) के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्तावों को तैयार करते हैं और उन्हें स्कीम के तहत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) से अनुमोदित कराते हैं। संबंधित एसएलएसएमसी के अनुमोदन के बाद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा केन्द्रीय सहायता के अनुमोदन हेतु मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आवासों की अपनी शेष सभी मांग के परियोजना प्रस्तावों को मार्च/अप्रैल, 2020 तक स्वीकृत कराने का अनुरोध किया गया है कि ताकि वर्ष 2022 तक सभी आवासों के निर्माण को उत्तरोत्तर पूरा किया जा सके।

1,57,297 करोड़ रू. की केन्द्रीय सहायता से शहरी गरीबों (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणियां) के लिए कुल 100,85,691 आवास स्वीकृत किए गए हैं; जिसमें से 59,903 करोड़ रू. की राशि जारी की जा चुकी है। पीएमएवाई (यू) के तहत पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के दौरान शहरी गरीबों हेतु स्वीकृत और जारी केन्द्रीय सहायता का विवरण अनुलग्नक-।। पर है।

दिनांक 12.03.2020 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3083 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।

**पीएमएवाई (यू) के तहत पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान निर्मित आवासों के साथ-साथ निर्मित कुल आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण**

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्माण पूर्ण किए गए / सुपुर्द किए गए (सं.)*	पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के दौरान पूर्ण किए गए आवास (सं.)*		
			वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	20	-	-	20
2	आंध्र प्रदेश	3,26,229	3,299	29,791	2,60,223
3	अरुणाचल प्रदेश	1,829	-	16	1,308
4	असम	17,816	66	381	13,847
5	बिहार	68,045	12,184	2,100	37,464
6	चंडीगढ़ (यूटी)	5312	4963	57	154
7	छत्तीसगढ़	83,351	3307	3561	42,096
8	दादरा और नगर हवेली (यूटी)	2,228	103	366	1,167
9	दमन और दीव (यूटी)	874	3	65	291
10	दिल्ली (एनसीआर)	40,895	4244	2,487	17,579
11	गोवा	1,041	10	99	392
12	गुजरात	3,76,814	28,928	48,726	1,96,550
13	हरियाणा	21,266	549	2,093	10,535
14	हिमाचल प्रदेश	3653	43	202	1,858
15	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	6994	203	179	3286
16	झारखंड	78,449	3886	26,421	31,343
17	कर्नाटक	1,65,384	11,920	31,087	94,920
18	केरल	72,738	301	3809	42,691
19	लद्दाख (यूटी)	370	-	-	280

20	लक्षद्वीप (यूटी)	-	-	-	-
21	मध्य प्रदेश	3,20,079	5316	39,119	2,19,728
22	महाराष्ट्र	2,85,806	13,621	35,162	1,20,918
23	मणिपुर	3,841	24	177	2,231
24	मेघालय	1,007	248	27	450
25	मिजोरम	3,524	118	188	632
26	नागालैंड	4,119	494	89	1,394
27	ओडिशा	67,525	2,771	2,376	46,075
28	पुदुचेरी (यूटी)	3,407	79	51	1,899
29	पंजाब	23,413	338	1,860	9335
30	राजस्थान	80,511	4256	8204	21,641
31	सिक्किम	244	1	2	61
32	तमिलनाडु	2,92,097	6593	34,004	1,57,589
33	तेलंगाना	99,367	2,792	3,140	58,171
34	त्रिपुरा	42,551	161	7303	28,663
35	उत्तर प्रदेश	4,33,245	9639	12,005	2,97,627
36	उत्तराखंड	15,256	1,460	1,986	5669
37	पश्चिम बंगाल	1,89,579	7191	30,765	89,509
<b>कुल योग :-</b>		<b>32,15,926 ^</b>	<b>1,29,111</b>	<b>3,27,898</b>	<b>18,17,596</b>

\* पूर्व जेएनएनयूआरएम के अपूर्ण आवास शामिल हैं।

^ वे 77,047 लाभार्थी शामिल हैं जिन्होंने ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के तहत बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) के माध्यम से हाल ही में आवास प्राप्त किए हैं

दिनांक 12.03.2020 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3083 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक II

पीएमएवाई (यू) के तहत पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान शहरी गरीबों के लिए स्वीकृत और जारी केंद्रीय सहायता का ब्यौरा		
विवरण	वित्तीय वर्ष	उपलब्धि
वर्ष-वार स्वीकृत केन्द्रीय सहायता	2016-17	14,244.80 करोड़ रु.
	2017-18	37,350.78 करोड़ रु.
	2018-19	57,262.87 करोड़ रु.
वर्ष-वार जारी केंद्रीय सहायता	2016-17	4,597.68 करोड़ रु.
	2017-18	15,967.28 करोड़ रु.
	2018-19	22,096.83 करोड़ रु.